

मोदी इस साल के अंत में जाएंगे कनाडा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के अंत में 11-12 दिसम्बर को कनाडा की यात्रा करेंगे। कैलगरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि यह दौरा टोरंटो और ओटावा में होगा। उन्होंने कहा कि हम इस दिसम्बर प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। कनाडा में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में इस यात्रा की जानकारी साझा की।

परिसीमन विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार

नई दिल्ली, देशबन्धु। वोट चोरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच एक बार फिर परिसीमन विधेयक को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर कहा है कि संसद का मानसून सत्र खत्म हुए 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह असाधारण परिस्थिति है। यदि सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती है तो उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। राजनीतिक दलों व अन्य हितधारकों को विधेयक के नए प्रावधानों को समझने और उस पर अपनी राय बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसके पहले भी खरगे दो बार 16 जुलाई और 27 अगस्त को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। ध्यान रहे कि 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन व इसमें शामिल परिसीमन विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया था, लेकिन दो तिहाई बहुमत नहीं होने के कारण यह गिर गया था। चर्चा है कि हाल के दिनों टीएमसी व शिवसेना (यूबीटी) आदि में हुई टूट के बाद सत्तारूढ़ एनडीए का आंकड़ा बढ़ा है। साथ ही भाजपा को डीएमके का भी साथ मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि परिसीमन विधेयक पर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को ही खत्म हो गया था, लेकिन सत्रावसान की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ऐसी सूरत में विशेष बैठक बुलाने का रास्ता खुला हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सरकार विशेष सत्र की तारीखें तय करने में जुटी हुई है। उधर सरकार के हर कदम पर विपक्ष ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। जब विशेष सत्र की अटकलें तेज हुई तो खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेज कर फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी। इसके पहले उन्होंने कांग्रेस का मत स्पष्ट करते हुए कहा था कि लोकसभा में 543 सीटों की स्थिति को अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखा जाए और महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण वर्ष 2029 से लागू हो।

- खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर लिखा पत्र
- वोट चोरी पर मचे घमासान के बीच विधेयक की अटकलें तेज

हवाई किरायों पर नियम तैयार

नई दिल्ली, (आईएएनएस)। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्कों को विनियमित करने के नियम तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही भरोसा दिलाया कि इन नियमों को दो सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, आर. महादेवन और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर जारी नियमों को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) से जुड़ा है। इसमें नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कथित 'अपारदर्शी, शोषणकारी और एल्गोरिदम-आधारित' मूल्य निर्धारण प्रथाओं और यात्रियों के लिए मुफ्त चेक-इन बैगेज की सीमा में की गई कटौती को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हवाई किराए में होने वाले अनिश्चित उतार-चढ़ाव खासकर त्योहारों, छुट्टियों और यात्रा के व्यस्त समय के दौरान किराए में होने वाली भारी बढ़ोतरी और एयरलाइनों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों से जुड़ी चिंताओं पर विचार कर रहा है। इससे पहले हुई एक सुनवाई में, जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले हवाई किराए में कुछ 'तर्कसंगतता' होनी चाहिए। साथ ही, पीठ ने केंद्र सरकार से हवाई यात्रियों को राहत देने का आग्रह भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, 'लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश करें। एक ही दिन, एक ही जगह जाने वाली उड़ानों के लिए, एक एयरलाइन इकॉनमी क्लास में 8,000 रुपए लेती है, जबकि दूसरी 18,000 रुपए लेती है। इसमें कुछ तर्कसंगत बदलाव होने चाहिए। केंद्र ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एयरलाइन की कीमतों और अतिरिक्त शुल्कों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' के तहत नियम बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जनहित याचिका (पीआईएल) में उठाए गए मुद्दों, जिनमें हवाई किराया, सर्ज प्राइसिंग और अतिरिक्त सामान (बैगेज) के शुल्क शामिल हैं, पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि आपातकालीन स्थितियों, त्योहारों और यात्रा के व्यस्त समय के दौरान टिकट की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से उन यात्रियों को परेशानी होती है, जिन्हें चिकित्सा, शिक्षा या रोजगार से जुड़े कारणों से यात्रा करनी पड़ती है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, दो सप्ताह में होंगे जारी

निविदा/नियुक्ति/जाहिरात

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार मो. शहजाद उर्फ गुड्डू पेंटर पिता मो. शहीद, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी के.जी. एन. नगर, टेढी नीम, गली नं-1, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, थाना-हनुमानताल तह. व जिला जबलपुर की तरफ से व उनके निर्देशानुसार आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार को उसके पुत्र मो. अहफाज उर्फ जोहान, उम्र लगभग 24 वर्ष के द्वारा मानसिक शारिरिक व आर्थिक रूप से अत्याधिक प्रताडित किये जाने के कारण मेरा पक्षकार अपनी जबलपुर में स्थित अचल संपत्ति एवं सम्पूर्ण संपत्ति से बेदखल करता है। उसका मेरे पक्षकार की सम्पूर्ण चल व अचल संपत्ति मे कभी भी कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं होगा एवं इसके अतिरिक्त उसके द्वारा भविष्य मे किसी भी क्रिया कलाप व लेन देन से मेरे पक्षकार का कोई संबंध नहीं रहेगा इस हेतु मेरे पक्षकार का पुत्र स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त कारणोवश मेरा पक्षकार अपने पुत्र से सभी रिश्तेनाते समाप्त घोषित करता है एवं मेरे पक्षकार के पुत्र के द्वारा किसी भी तरह की झूठी शिकायत पुलिस मे दिये जाने की हमेशा धमकी दी जाती है इस हेतु मेरे पक्षकार का पुत्र स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरा पक्षकार इनसे पृथक रह रहा है और कभी भी अप्रिय स्थिती के लिये जिम्मेदार नहीं होगें।

जबलपुर,
दिनांक 15/10/2026

शेख मंजूर, अधिवक्ता
म.प्र. उच्च न्यायालय
आफिस - रजा चौक से आनंद नगर रोड, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड जबलपुर
म.प्र. पिन नं.482002
मो.नं. 9300502817, 9425472482

रनं. 2685

In The Court Of III Additional District and Session Judge District Court, Jabalpur
presiding Officer: **श्री संतोष कुमार कोल**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC/ 0000008/2026)
शकुन बाई .....वादी
Vs
कृष्ण कुमार सेन .....प्रतिवादी
प्रो. 841/15/10/26
Process Id-/2026
पेशी दि.:-02/12/2026

प्रेषिती-
(1) आम जनता पता- जबलपुर

यह कि प्रार्थी शकुन बाई ने आपके विरूद्ध एम.जे.सी. के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 13 अक्टूबर 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- समाचार प्रकाशन हेतु नोटिस
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(संतोष कुमार कोल)
जिला न्यायाधीश (तृतीय)
सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)

कृति

In The Court Of I Civil Judge Class-II, District Court, Jabalpur
Presiding Officer:
सुश्री रूपा मिश्रा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु
(RCS A/0000096/2026)
बारेलाल पटेल.....वादी
Vs
स्टेट .... प्रतिवादी
Process Id-2026
पेशी दिनांक 23/11/2026

प्रेषिती
(1) आम जनता पता- प्रकाशन हेतु नोटिस

यह कि प्रार्थी बारेलाल पटेल ने आपके विरूद्ध आर.सी.एस.ए. के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 12 अक्टूबर 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- समाचार प्रकाशन
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(सुश्री रूपा मिश्रा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र)

रनं. 2696

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0028/अपील/2025-26
मझौली, दिनांक:-18.09.2026
1. हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी पिता भोलाराम ब्राम्हण 2. बाबूलाल चतुर्वेदी पिता भोलाराम ब्राम्हण 3. छोटेलाल चतुर्वेदी पिता भोलाराम ब्राम्हण
सभी निवासी ग्राम-चुवाही, तहसील-मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)
..... अपीलार्थीगण
बनाम
1. रामगोपाल पिता लेवहा यादव निवासी ग्राम-चुवाही. तहसील-मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)
2. अनुराग सिंह चौहान पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह चौहान निवासी मधुबन हाउस वार्ड नं. 19 डैनिहा, तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म.प्र.)
..... उत्तरवादीगण

आम-सूचना

एतद् द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01 रामगोपाल पिता लेदहा यादव निवासी ग्राम-चुवाही. तहसील-मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.) को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा ग्राम-चुवाही के भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील-मझौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0835/अ-6/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 01 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु उत्तरवादी क्रमांक 01 उपस्थित नहीं हुये है। जिस संबंध में दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कर उत्तरवादी क्रमांक 01 को एक अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः उत्तरवादी क्रमांक 01 को सूचित किया जाता है कि नियत पेशी दिनांक 19.10.2026 के पूर्व अपना पक्ष समर्थन रख सकते हैं। बाद म्याद प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नही किया जावेगा। विधि संगत आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी
मझौली जिला सीधी (म.प्र.)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./10602/22/D-12/MPRRDA/2026 Bhopal, Dated : 16.10.2026

NOTICE INVITING TENDER No. 1307 UPG

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below.
● **Name of work : UPG (MPRRDA SSR : 01.01.2024)**

S. No.	Name of District	No.of Package	Total PAC (In Rs.)
1.	Balaghat	1	26839000.00
2.	Dewas	1	9705186.00
3.	Dhar	1	39369000.00
4.	Sagar	3	43357000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **28.10.2026 from 17:30 hrs.** and last date for online bid submission is **11.11.2026 (17:00 hrs.)**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)
M.P. Madhyam/128643/2026

'मेरी सड़क' ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

कार्यालय कलेक्टर (समग्र शिक्षा) जिला अनूपपुर म.प्र.

दिनांक:- 16.10.2026

(विज्ञप्ति)

संचालक राशिके. के पत्र क्रमांक 334 भोपाल दिनांक 22.09.2026 के परिपालन में मूल्यांकन कार्य प्रश्नपत्र मुद्रण हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से BIDGEM/2026/B/8171060 प्रकाशित की गयी है सभी संबंधित बिडर्स की ओर सूचनार्थ ।

जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा,
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

सरदार पटेल लॉ कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय- सरदार पटेल लॉ कॉलेज, कुंडम रोड, पिपरिया, खमरिया, जबलपुर (म.प्र.), फोन- 0761-2997742

विश्वविद्यालय अधिनियम कोड 28 के अंतर्गत निम्न अनुसार नियुक्ति हेतु आवेदन की शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं दो फोटो सहित आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 07 दिवस तक। विवरण निम्नानुसार..

क्र.	पद	पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1.	सहायक प्राध्यापक (इतिहास)	01	एम.ए. (Ph.D./NET/SLET अनिवार्य)

नोट- 1. संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ Ph.D./NET/SLET अनिवार्य । 2. उपरोक्त पदों के लिए यूजीसी चयन के प्रभावशाली नियम लागू होंगे। 3. आरक्षण में यूजीसी एवं मध्य प्रदेश शासन नियमों का पालन आवश्यक होगा। 4. आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय के संचालक / प्राचार्य के पते पर सीधे या डाक द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे । 5. **Email id: sardarpatellawcollege@gmail.com** 6. अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर 9826342454 पर संपर्क कर सकते है।

प्राचार्य, सरदार पटेल लॉ कॉलेज जबलपुर

आधार नहीं तो भी नहीं रुकेगा सरकारी लाभ

नई दिल्ली, (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने और आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आधार उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें पहचान की जांच करने, बायोमेट्रिक सत्यापन में नाकामी की स्थिति से निपटने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के फायदे से वंचित होने से बचाने के प्रावधान शामिल हैं। इसका उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान वास्तविक लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, यह नियम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अधिसूचना में आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, पहचान की पुष्टि करने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या आने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इन प्रावधानों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी परेशानी या आधार उपलब्ध नहीं होने के कारण पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाएं। नए नियमों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ से वंचित होने से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएं। इसका मतलब है कि आधार से जुड़ी दिक्कत या बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी होने पर पात्र लोगों के हितों की रक्षा करने की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है।

कार्यालय अधीक्षक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर (म.प्र.)

सी.सी.टी.वी. सिस्टम की ए.एम.सी. वर्ष-2026-27
-: प्रथम वार्षिक ई-निविदा सूचना :-

पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों से केन्द्रीय जेल जबलपुर में स्थापित सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस सिस्टम के वार्षिक रख-रखाव तथा मरम्मत की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु ए.एम.सी. के लिये ई-निविदा पोर्टल **https://gem.gov.in/** पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक एवं समय	स्थान
1	प्री-बिड मीटिंग	दिनांक 27/10/2026 को समय प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर
2	ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अन्तिम तिथि (निविदा फार्म शुल्क Gem पोर्टल के अनुसार देय होगा)	दिनांक 06/10/2026 सायंकाल 5.30 बजे तक	https://gem.gov.in/
03	तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 07/10/2026 को प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर
04	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 13/11/2026 को प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर

निविदा फॉर्म एवं निविदा से संबंधित जानकारी वेबसाइट **https://gem.gov.in/** पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा फॉर्म प्रदर्शित वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।

निविदा कार्यक्रम में तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों से परिवर्तन हो सकता है, जिसकी जानकारी जेम **(GEM)** पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अतः समस्त इच्छुक निविदाकार निविदा से संबंधित अद्यतन **(Updated)** जानकारी प्राप्त करने हेतु निरंतर जेम पोर्टल का अवलोकन करते रहें।

जेल अधीक्षक
नेताजी सुभाषचंद्र बोस,
केन्द्रीय जेल, जबलपुर

G-20114/26 स्वच्छता ही सेवा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन विभाग, मंडल कार्यालय: 1227, शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)– 482001
Email- cojbprec@pnb.co.in, Telephone: 0761-4924461

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई– नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/ सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रूपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है :

ई–नीलामी दिनांक एवं समय– 26.11.2026 दोपहर 12:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकाल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 26.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 10000/- (रूपए दस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/ बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा: फव्वारा चौक, जबलपुर **1. श्री पवन कुमार मंडल पिता श्री विष्णु मंडल** **(उधारकर्ता एवं गिरवीकर्ता)** पता 1: म.नं. 304/21ई, गोहलपुर थाने के पीछे, चितरंजन वार्ड, अमखेड़ा मार्ग, अमखेड़ा, तहसील एवं जिला– जबलपुर (म.प्र.)– 482004 पता 2: वार्ड नं. 74, कुदवारी, महाराजपुर, तहसील– पनागर, जिला– जबलपुर (म.प्र.) **2. श्रीमति राधिका मंडल पत्नि श्री पवन कुमार मंडल** **(उधारकर्ता एवं गिरवीकर्ता)** पता 1: म.नं. 304/21ई, गोहलपुर थाने के पीछे, चितरंजन वार्ड, अमखेड़ा मार्ग, अमखेड़ा, तहसील एवं जिला– जबलपुर (म.प्र.)– 482004 पता 2: वार्ड नं. 74, कुदवारी, महाराजपुर, तहसील– पनागर, जिला– जबलपुर (म.प्र.) A/C 193700NC03484958	सम्पत्ति का समस्त भू भाग अचल आवासीय सम्पत्ति स्थित– मौजा– कुदवारी, एस.नं. 503, प.ह.नं. 26 (पुराना), 80 (नया), पटवारी डाय. खसरा नं. 58/1/1/1/1 का भाग, वार्ड नं. 74, एरिया 20x33 = 660 वर्गफुट, वार्ड नं. 74, रा.नि.मं.– महाराजपुर, तहसील– पनागर, जिला– जबलपुर (म.प्र.), जिसकी सीमा इस प्रकार है– उत्तरः जगन्नाथ सेन का मकान, दक्षिणः विक्रेता का मकान, पूर्व– साईड रोड, पश्चिमः दीपक गुप्ता का मकान। स्वामी एवं बंधककर्ता– श्री पवन कुमार मंडल पिता श्री विष्णु मंडल एवं श्रीमति राधिका मंडल पत्नि श्री पवन कुमार मंडल। नीलामी संदर्भ संख्या **PUNB1937200724**	**अ) 17.02.2025** **ब) 16.09.2025** **स) सांकेतिक** **द) 8,32,547.03/-** + ब्याज एवं अन्य व्यय	**अ) ₹ 17,56,350/-** **ब) ₹ 1,75,635/-** **स) 26.11.2026** **द) ₹ 10,000/-**
2. शाखा: सिवनी, जिन्ना चौक (म.प्र.) **ऋणी: 1) मेसर्स सुप्रिया ट्रेडर्स** के नाम से उनका व्यापार है, पताः 148/1 बस्ती, चक्की खमरिया, सिवनी (म.प्र.)– 480661 **प्रोपराइटरः 2) श्री दीपक सोनी पिता श्री फागू सोनी,** आवासीय पताः 148/1 बस्ती, चक्की खमरिया, सिवनी (म.प्र.)– 480661 प्रोपराइटर मेसर्स सुप्रिया ट्रेडर्स **जमानतदार/बंधककर्ताः 3) श्री फागू सोनी पिता श्री कल्लू सोनी,** आवासीय पताः 148/1 बस्ती, चक्की खमरिया, सिवनी (म.प्र.)– 480661 मेसर्स सुप्रिया ट्रेडर्स द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए गरंटर एवं बंधककर्ता के रूप में खड़े हैं। A/c No.0490008700003575	सम्पत्ति का समस्त भू भाग अचल सम्पत्ति एवं उस पर निर्माण स्थित– मौजा– चक्की खमरिया, पी.सी.नं. 01 (चक्की खमरिया), आर.आई.सी. सुकतरा, तहसील खुरई, जिला– सिवनी (म.प्र.)– 480661, खसरा नं. 400/5, एरिया– 100 वर्गमीटर (1076 वर्गफुट)। मोहन सोनी की सम्पत्ति की सीमाः उत्तर– सांई मंदिर की सीसी रोड, दक्षिणः श्री संतोष सोनी का मकान, पूर्व– श्री राजकुमार सोनी का मकान, पश्चिमः बंधककर्ता श्री फागू सोनी पिता श्री कल्लू सोनी। नीलामी संदर्भ संख्या **PUNB0C00181651**	**अ) 07.04.2026** **ब) 28.07.2026** **स) सांकेतिक** **द) 37,13,404.28/-** + ब्याज एवं अन्य व्यय	**अ) ₹ 20,87,000/-** **ब) ₹ 2,08,700/-** **स) 26.11.2026** **द) ₹ 10,000/-**

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें: (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। (2) संपत्तियों की बिक्री "जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर होगी। (3) ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (4) विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई– नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। (5) संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

स्थान: जबलपुर, दिनांक: 17.10.2026 **पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी**

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल | प्रॉपर्टी फॉर सेल

विस्तृत जानकारी एवं ई-पंजीयन की सुविधा www.mphousing.in, www.mponline.gov.in कियोस्क पर उपलब्ध

नया घर खरीदने का सुनहरा अवसर
सहस्त्रधारा गौंजी जिला मण्डला में मण्डल द्वारा निर्माणाधीन कॉलोनी में स्वतंत्र भवन क्रय करने का सुनहरा अवसर
(रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर P-MDL-19-2422)

ई-पंजीयन 18.11.2026 तक आमंत्रित

क्र.	भवन का प्रकार	उपलब्ध भवनों की संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (रु. लाख)	पंजीयन राशि (रुपये)	आवेदन शुल्क (रुपये)
1.	18 ई.डब्ल्यू.एस. भवन	16	52.50	30.01	916000/-	82450/-	236/-
2.	32 एल.आई.जी.	28	63.25	36.51	1316000/-	118450/-	236/-
3.	20 जूनियर

TRANSGLOBE ADVISORS

Your Trusted Management Advisory

www.transglobeadvisors.in

The Pioneer
BHOPAL | SATURDAY | OCTOBER 17, 2026

Supreme Court stays trial in Twisha Sharma case

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday stayed the ongoing trial in the unnatural death case of former model Twisha Sharma before a Bhopal sessions court and issued notices to the CBI, her husband Samarth Singh and mother-in-law Giribala Singh on a plea seeking transfer of the proceedings to a Delhi court.

A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi passed the order on a petition filed by Twisha's father, Navnidhi Sharma, who expressed apprehension that his daughter's case may not receive a fair trial in Madhya Pradesh.

Navnidhi Sharma cited the influence of his daughter's mother-in-law, a retired district judge.

Twisha, 33, was found hanging at her marital home in Bhopal's Katara Hills area on May 12. Her family accused her in-laws of dowry harassment and abetment to suicide. Her in-laws claimed she suffered from drug addiction. Police registered an FIR against her husband and her mother-in-law on charges of dowry harassment.

Senior advocates Siddharth Luthra and Siddharth Aggarwal, along with advocate Abhijeet Sinha, appeared for Navnidhi Sharma. The petitioner sought transfer of the trial to Delhi on grounds that he is settled in the Delhi-NCR region.

The case is pending before a district and additional sessions judge in Bhopal.





As of October 10, the proceedings had reached the stage of arguments on the framing of charges.

The apex court had taken suo motu cognisance of Twisha's death in May this year amid concerns over the fairness of the investigation by the Madhya Pradesh police. The probe was subsequently transferred to the CBI.

On May 25, the CJI-led bench said it was "pained" by the narrative that the judiciary was shielding the accused. It said it would ensure a fair, independent, and impartial CBI probe into the death of the former model-turned-actor.

The initial FIR was registered under Sections 80(2), 85 and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), relating to dowry death, cruelty by a husband or his relatives, and common intention, respectively. Sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, which deal with giving or taking dowry and demanding dowry, were also invoked.

Following investigation, the CBI dropped the dowry-death charge against Giribala Singh and invoked Section 108 of the BNS, which deals with abetment of suicide. According to the prosecution, she allegedly abetted Twisha's suicide by taunting and harassing her.

Giribala Singh was granted anticipatory bail by the Bhopal trial court on May 15.

The Madhya Pradesh Government and Twisha's parents challenged the order before the high court, which quashed her anticipatory bail on May 27.

Order Order

SC issues contempt notice to Raut over remarks on CJI



The Supreme Court on Friday issued show-cause notices to Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP Sanjay Raut and journalist Nikhil Wagle in criminal contempt proceedings over their public remarks concerning Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and the judiciary.

A bench comprising the CJI and Justice Joymalya Bagchi, however, exempted Raut and Wagle from personal appearance on the next date of hearing, saying it would first consider their explanations.

The show-cause notices were issued on a contempt plea filed by the Supreme Court Bar Association (SCBA).

SCBA President and senior advocate Pradeep Rai alleged that the remarks by Raut and Wagle went beyond the bounds of fair criticism and were capable of undermining public confidence in the Supreme Court.

Expressing concern over statements targeting the judiciary, the CJI observed that courts had consistently upheld personal liberty and fundamental rights, making attacks on the institution particularly unfortunate.

The SCBA pressed for the personal appearance of the respondents. The bench, however, decided to issue show-cause notices first.

"We are giving a show-cause as of now. Of course we are granting exemption for personal appearance. Let us see," the bench said. (*PTI*)

SC seeks response from Centre on child social media safety



The Supreme Court on Friday sought replies from the Centre and the National Commission for Protection of Child Rights on a PIL filed by an Indore-based school seeking a comprehensive and enforceable national framework to protect children from the alleged risks associated with social media platforms. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi took note of the plea filed by Emerald Heights International School and its director of academics, Siddharth Singh Girnar, and issued notices to the ministries of women and child development and law and justice, and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). The bench tagged the plea, filed by Vaibhav Choudhary, with a pending petition and listed it for hearing on December 7. "Issue an appropriate writ, order or direction declaring that the continuing failure of the respondents to provide effective protection to children against foreseeable risks of grooming, sexual exploitation, cyber-bullying, exposure to age-inappropriate and harmful content, behavioural profiling, compulsive-use design and other harms associated with commercial social media platforms is arbitrary, unreasonable and violative of Articles 14, 15(3), 21 and 21A of the Constitution," the plea said.

It called for mandatory age verification, age-appropriate access, verifiable parental consent and stronger safeguards against cyberbullying, sexual exploitation, harmful content and excessive platform use.

The plea also sought a direction to the Centre to frame, notify and operationalise a dedicated, comprehensive and enforceable regulatory framework for the protection of children from harms arising from their access to and use of social media platforms. "Issue a writ of mandamus directing the Centre to prohibit the use of social media platforms by children below such age as may be prescribed, and to regulate the use of such platforms by children above the said age, in such manner as may be found appropriate," the plea said. It also sought a direction to the Centre to "frame and enforce appropriate age-based restrictions on the creation, maintenance and use of accounts by children on designated social-media platforms". The petitioner school referred to instances of underage children operating social media accounts, being contacted by strangers, facing cyber-bullying and harassment, and experiencing sleep deprivation and reduced concentration following prolonged use of mobile phones. The plea also cited concerns raised by parents over children's excessive screen time, anxiety about online popularity, body-image issues, social withdrawal and declining interest in studies and outdoor activities. (*PTI*)

Delhi Police lodges kidnapping case against mother over cross-border child removal to Australia

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

A city court directed criminal FIR in Delhi has brought allegations of forged parental consent in an India–Australia child removal case into focus, raising a public-interest question: how are children protected when the authenticity of documents supporting international travel and visa applications is disputed?

Damanjeet Singh, the child's biological father, has alleged that his two-and-a-half-year-old son was taken from India to Australia without his authorisation.

He alleged that his original Indian passport was stolen and that his signatures were forged on documents submitted in connection with the child's Australian visa application, including Australian Visa Form 1229.

He further alleged that this involved a coordinated conspiracy by an organized syndicate rather than a single individual. The central issue



is whether the consent relied upon was genuine and whether the documents accurately established the legal authority required for the child's visa and relocation. The allegations remain subject to investigation and judicial determination.

According to the case details supplied by the complainant, proceedings were initiated through his counsel, Advocate Monika Verman, under Section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), which provides for a competent Magistrate to order a police investigation subject to statutory requirements.

Judicial Magistrate First Class Vikas Madaan, JMFC-07, West District, Tis Hazari Courts, New Delhi, reportedly directed Tilak Nagar Police Station to register the case. The complainant states that FIR No. 0393/2026 was subsequently registered against the child's mother under Sections 137(2), 336(3) and 340(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), concerning punishment for kidnapping, forgery intended for cheating and the fraudulent or dishonest use of a forged document as genuine.

The FIR brings the allegations into the criminal-investigation process. Its registration does not establish guilt, and the applicability of the cited offences—including questions of lawful guardianship, consent and document authenticity—must be determined on the evidence.

Australian Visa Form 1229 is used to record consent to the grant of an Australian visa to a child under 18. Depending on the applicable visa requirements and family circumstances, consent may be required from persons legally entitled to determine where the child lives, unless another lawful basis is established, such as a relevant court order or evidence of sole parental responsibility.

Delhi riots : SC adjourns hearing on Athar's bail plea

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday adjourned for four weeks the hearing on a bail plea filed by Athar Khan in a case under the anti-terror law UAPA concerning the "larger conspiracy" behind the February 2020 riots in northeast Delhi.

A bench of Justices Aravind



Kumar and Vipul M Pancholi deferred the matter after Additional Solicitor General S V Raju informed it that a reply has been filed in the matter. The top court allowed Khan rejoinder to the reply filed by Delhi police.

The apex court had earlier issued a notice to Delhi Police on an appeal filed by Khan challenging a Delhi High Court judgment dated July 7 refusing bail to him.

The high court had dismissed Athar's appeal challenging a trial court's January 29 order that denied him relief in the case, stating that he was but "one of the main conspirators who conspired to cause deaths during the riots" and not a "mere local-level operator".

Athar's lawyer had sought bail on the grounds that he was a "local-level facilitator" who had been in custody for six years, and that similarly placed co-accused had been granted bail by the Supreme Court. The high court bench had considered the Supreme Court's findings on the bail pleas by the co-accused and held that Athar's role was "clearly distinguishable" from those given relief by the apex court. It said the material, including a protected witness statement, showed that while others on a WhatsApp group chat suggested non-violent protests, Athar "persisted with his objective of engaging in violent protests, to the extent of even causing death".

The high court said that since Athar's prima facie role in causing deaths and destruction of private and public property was established, his case did not pass the strict test for bail under Section 43D(5) of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967.

SC allows PFI chairman Abubacker to undergo treatment at Delhi hospital



PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday allowed Popular Front of India's (PFI) founding chairman E Abubacker, arrested in a case under anti-terror law UAPA, to undergo treatment at a Delhi hospital but imposed certain conditions.

A bench of justices MM Sundresh and PB Varale directed him to bear the expenses of treatment at Max Super Speciality Hospital, Saket and said he shall be accompanied by one family member.

"Petitioner shall also pay requisite charges for escort. We make it clear attendant should not carry objectionable items. We request the hospital to file a report on further course of treatment required along with possible period of stay. Cost of hospital shall be borne by the petitioner," the bench said.

Justice Sundresh orally remarked that the court cannot be insensitive towards things and as a judge "you have to mix it with some sympathy".

During the hearing, Additional Solicitor General SV Raju, appearing for the National Investigation Agency (NIA), submitted that Abubacker may be sent to Max hospital for treatment for one week. "Secondly, no devices in hospital. Thirdly, no outsiders can meet him in the hospital. Police will be outside the room at his cost," Raju said.

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHOPAL
Water Work Department
Municipal Corporation Rest House, Shyamla Hills, Bhopal Ph.no. 0755-2701669

NOTICE INVITING e-TENDER

Online tenders are being invited for the following work from the appropriated firm that Registered in the office of Madhya Pradesh (Central Registration Cell). The tender documents can be obtained online on the website http://mptenders.gov.in as per the Key Dates in the Notice published on the above website and detailed information can also be seen on website http://mptenders.gov.in. Corrigendum for this NIT shall not be issued separately in news papers. Corrigendum regarding correction can be seen on the website. http://mptenders.gov.in

S. No.	NIT No.	Tender ID	Details of Work	Estimated Cost (INR)	Earnest Money (EMD)	Bid Submission End Date
1	2	3	4	5	6	7
1	First Call	2026_UAD_543855_1	Outsourcing of man power required for operation and maintenance of 50 MLD Manuabhan Tekri Water Treatment Plan comprising Karbala Raw water Pump House, 33Kv Substation at Karbala, 5954 meters Raw Water Pipe line from karbala intake well to Manuabhan Tekri WTP Under, Bhopal	109,51,932.00	1,09,519.00	16.11.2026 05.30 PM

T.N. 902/026/027

Executive Engineer
Water Work Department
Municipal Corporation, Bhopal

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
(CO-SAM), Circle Office: 1227,
Shaleen House, Napier Town, Jabalpur (M.P.)- 482001
E-mail: cojbprec@pnb.co.in, Telephone: 0761-4924461

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE for Sale of immovable assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) & 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property(ies) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the symbolic/physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer the Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on date as mentioned herein below for recovery of amount due to Punjab National Bank Secured Creditor from below named borrower(s), /mortgagor(s) and guarantor(s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned below against the respective properties. A short description of the immovable property(ies) with known encumbrances, if any, are mentioned as under.

Date and time of E-auction: 26.11.2026 between 12.00 p.m. to 05.00 pm. (with extension of 10 minute duration after 5.00 pm, if required). Last date of submission of EMD- 26.11.2026 till 12.00 p.m.

THE BIDDER SHALL IMPROVE THE BID OFFER IN MULTIPLE OF RS. 10,000/- (RUPEES TEN THOUSAND ONLY)

Borrower/Mortgagor / Guarantor Name	Description of Immovable Properties / Secured Assets	A)Demand Notice Date B) Possession Date C) Name of Possession D) Amount due to bank (as per demand notice)	A)Reserve Price (Rs.) B) EMD (Rs.) C) Last Date of Deposit of EMD D) Bid Increase Amount
1. Branch: Fawara Chowk, Jabalpur **1. Shri Pawan kumar Mandal S/O Shri Vishnu Mandal (Borrower and Mortgagor)** Address 1: H NO 304/21E, Behind Gohalpur Thana, Chitranjan Ward, Aamkheda Marg, Aamkheda, Tehsil and Distt.-Jabalpur (M.P.),482004 Address 2: Ward no 74,Kudwari ,Maharajpur, Tehsil-Panagar, Distt.- Jabalpur (M.P.) **2. Smt. Radhika Mandal W/o Shri Pawan kumar Mandal (Borrower and Mortgagor)** Address 1: H NO 304/21E, Behind Gohalpur Thana,Chitranjan Ward, Aamkheda Marg, Aamkheda, Tehsil and Distt.-Jabalpur(M.P.),482004 Address 2: Ward no 74, Kudwari, Maharajpur, Tehsil-Panagar, Distt.- Jabalpur(M.P.) A/C 193700NC03484958	**All that part and parcel of immovable Residential Property Situated at- Mauza- Kudwari, S No 503, PH No 26 (Old), 80 (New), Part of Patwari Div. Khasra No. 58/1/1/1/1, Ward No 74 Admeasuring Area-20x33= 660 Sq.Ft., Ward No 74, RNM-Maharajpur, Tehsil- Panagar, Distt- Jabalpur (M.P.), Boundaries**- North- House of Jagannath Sen, South- House of Seller, East- Side Road, West- Houe of Deepak Gupta. Owner & Mortgagor- Shri Pawan kumar Mandal S/O Shri Vishnu Mandal and Smt. Radhika Mandal W/o Shri Pawan kumar Mandal . **Auction Ref No. PUNB1937200724**	**A) 17.02.2025** **B) 16.09.2025** **C) Symbolic** **D) 8,32,547.03/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 17,56,350/-** **B) ₹ 1,75,635/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**
2. Branch: PNB Betul 008100 (MP) **1. Shri Charanjit Parothi S/O Kaluram Parothi (Borrower & Mortgagor)** **2. Smt Nidhi Parothi w/o Shri Charanjit Parothi (Borrower & Mortgagor)** Both Above at Address: 181G Lohiya Ward, Near Mata Mandir, Ganj Betul, Tehsil & Distt. Betul, BETUL, Madhya Pradesh, Pin 460001 A/c No. 0081009900000188 008100NT00000036	**All that part and parcel of the property Consisting of one Flat No. 302 C, at Third Floor, Block-C (Yashoda Heights), Teh. & Dist. Betul M.P. total Super Built-up Area 59.10sq-m, Builtup area 506sq-ft = 47.02sq-m in the name of Shri Charanjit Parothi & Smt Nidhi Parothi at Humlapur, Arjun Ward No. 2G, Gokuldham (Yashoda Heights), PH No. 53 New 49, B. No. 713, Kh. No. part of 2/1, 2/2, 3. BOUNDARIES AS-** NORTH- Flat No. 301 C, SOUTH- Open Duct (Govinda Heights), EAST- Flat No. 304C, WEST- Garden & Nala. **PROPERTY IDPUNBQQB60673858**	**A) 17.09.2025** **B) 26.11.2025** **C) Symbolic** **D) 1745480.30/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 18,60,000/-** **B) ₹ 1,86,000/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**
3. Branch: Seoni, Jinna Chowk (MP) **Borrower: 1) M/s Supriya Traders,** having its business address at 148/1 Basti, ChakkiKhamariya, Seoni (M.P.) - 480661. **Proprietor: 2) Shri Deepak Soni S/o Shri Phaggu Soni,** residing at 148/1 Basti, ChakkiKhamariya, Seoni (M.P.) - 480661, Proprietor of M/s Supriya Traders. **3) Guarantor/Mortgagor: Shri Phaggu Soni S/o Shri Kallu Soni,** residing at 148/1 Basti, Chakki Khamariya, Seoni (M.P.) - 480661, standing as Guarantor and Mortgagor for the credit facilities availed by M/s Supriya Traders. A/c No.0490008700003575	**All that piece and parcel of immovable property together with the construction standing thereon, situated at Mouza Chakki Khamariya, PCN No. 01 (ChakkiKhamariya), RIC Suktara, Tehsil Kurai, District Seoni (M.P.) - 480661, bearing Khasra No. 400/5, admeasuring 100 Sq. Mtr. (1076 Sq. Ft.), Bounded By the property of Shri Mohan Soni** on the North, CC Road leading to Sai Mandir on the South, the house of Shri Santosh Soni on the East, and the house of Shri Rajkumar Soni on the West, owned and mortgaged by Shri Phaggu Soni S/o Shri Kallu Soni. **Auction Ref No. PUNB0C00181651**	**A) 07.04.2026** **B) 28.07.2026** **C) Symbolic** **D) 37,13,404.28/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 20,87,000/-** **B) ₹ 2,08,700/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**

Details of encumbrances known to the secured creditor: Not known

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AND SARFAESI ACT, 2002

TERMS AND CONDITIONS: (1) The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions. (2) The properties as being sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "AS IS WHATEVER THERE IS"** basis. (3) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. (4) The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website- **https://baanknet.com,** on mentioned dates at the given time. (5) For detailed terms and conditions of the sale, please refer to **www.pnbindia.in, https://baanknet.com.**

Date: 17.10.2026, Place: Jabalpur

Authorised Officer, Punjab National Bank